३६४

विशेष फ़ाइल

अत्यंत गोपनीय

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के प्रतिनिधियों का केंद्रीय समिति ए-यूसीपी(बी) के सदस्यों के साथ ४ और ६ फ़रवरी १९५१ को हुई चर्चा का आशुलिपिक दस्तावेज़.

परिचय

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के प्रतिनिधियों के बीच फ़रवरी १९५१ में हुई चर्चा ने भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के इतिहास में एक निर्णायक भूमिका निभाई हैं. जोशी और बी.टी. रणदिवे के नाम से पहचान बनाने वाली पार्टी के लगातार दो नेतृत्वों के बाद भाकपा की वास्तविक राजनीतिक, वैचारिक, और संगठनात्मक पतन के परिणामस्वरुप वें आवश्यक हुई थीं.

पी.सी. जोशी के नेतृत्व को अन्य बातों के साथ १९४७ के माउंटबेटन अवार्ड का स्वागत करने, दक्षिणपंथी भटकाव के आगे घुटने टेक देने, तेलंगाना संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास करने और पार्टी को कांग्रेस पार्टी के नेहरू गुट के अधीनस्थ करने के रूप में माना गया था.

१९४८ में आयोजित भाकपा के द्‌वितीय कांग्रेस ने दक्षिणपंथी पी. सी. जोशी के नेतृत्व को तो अस्वीकार कर दिया लेकिन बी. टी. रणदिवे के निर्देशन में एक बाम-जोखिम भरा रास्ता अपनाया गया जो मजदूर वर्ग और किसानों की सक्रियता की वास्तविक संभावनाओं से काफी दूर था. (जोशी) की तरह रणदिवे

ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के निरंतर पकड़ को नकार कर, भारतीय पूंजीपति वर्ग की शक्ति को बढ़ा चढ़ा कर और देश में सामंतवाद के अवशेष की व्यापकता को कम आंक कर 'गैर-उपनिवेशीकरण' के सिद्धांत के आगे घुटने टेक दिया। ये त्रुटियां लोकतांत्रिक और समाजवादी क्रांतियों के गुंथन के सिधांत को अपनाने से आया जिसने जोरदार तरीके से भारत में लोगों की लोकतांत्रिक क्रांति की अवस्था के औचित्य से इनकार किया. भाकपा के द्‌वितीय कांग्रेस में यूगोस्लाव प्रतिनिधियों - यूगोस्लाव कम्युनिस्ट पार्टी पिछड़े देशो में क्रांति के विभिन्न चरणों के गुंथन के सिद्धांत का रचयिता थी- की भागीदारी को रणदिवे की दिशा अपनाने में मददगार होने के रूप में स्वीकार किया गया है जिसे इस अवधि के कम्युनिस्ट साहित्य में ठीक ही त्रोत्स्किवादी और टिटोवादी भटकाव के रूप में चित्रित किया गया है. मौजूदा पार्टी दस्तावेजों के संकलन इन बातों को उजागर करने के बजाय और धुंधला बनाते हैं.

प्रसिद्ध कोमिन्फोर्म का संपादकीय लोकतांत्रिक और समाजवादी क्रांतियों के गुंथन करने के प्रयास की त्रुटि पर, एक अर्द्ध-औपनिवेशिक और अर्द्ध सामंती देश, जहां कृषि क्रांति एक प्रमुख भूमिका अदा कर सकती है, की आवश्यकताओं के अनुकूल भारत में लोगों की लोकतांत्रिक क्रांति की अवस्था की आवश्यकता इंगित करते हुए भाकपा का मार्गदर्शन करने का प्रयास था. यह 'चीनी पथ' के रूप में प्रस्तुत किया गया था. तब, और आज भी, यह चीनी क्रांति की परिस्थितियों से उपजे संघर्ष के विशेष रूप को अपनाने के रूप में भारत में गलती से समझ लिया गया था. कोमिन्फोर्म का संपादकीय भाकपा नेतृत्व के विभिन्न घटकों के बीच मतभेदों को हल नहीं कर पाया जो तब सीपीएसयु (बी) के नेतृत्व की सलाह लेने के लिए प्रेरित हुए.

४ और ६ फरवरी को आयोजित बैठकें सीपीएसयु (बी) के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल मालेंकोव, सुस्लोव और युदीन और भाकपा के राजेश्वर राव, डांगे, घोष और बसवापुन्नैया के बीच हुई. भाकपा नेतृत्व ने मौखिक रूप से पार्टी नेतृत्व के सामने खड़ी समस्याओं का एक खाका प्रस्तुत किया और बदले में सीपीएसयु (बी) के नेताओं ने पार्टी और आंदोलन के मौजूदा हालात पर कई सवाल खडें कियें. इसके अलावा सीपीएसयु (बी) के नेतृत्व के पास पहले ही संदर्भ के लिए पार्टी के प्रमुख दस्तावेजों की एक मोटी फाइल थी जिसे विशेष रूप से इन चर्चाओं के लिए रूसी में अनुवाद किया गया था.

भाकपा नेताओं ने एक-एक करके १९४७ के बाद की अवधि में भाकपा नेताओं के अलग-अलग विचारों के विकास, भारतीय राज्य के चरित्र चित्रण; भारतीय क्रांति की अवस्था; क्रांति की चीनी पथ की व्याख्या; शहरों और ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र गतिविधि की भूमिका और विशेष रूप; हथियारबंद गतिविधि के लिए संघर्ष के कानूनी रूपों के संबंध; तेलंगाना संघर्ष के महत्व का मूल्यांकन; नेहरू सरकार की शांति नीति और उसके कोरिया नीति के प्रति अपनाये जाने वाला रवैया; विश्वासघात के संदिग्ध पार्टी के सदस्यों को मौत की सजा देने की पार्टी की जायज़ता या कुछ और; सत्ता के लोकतांत्रिक अंगों के निर्माण के पूर्व जमींदारों और व्यापारियों की संपत्ति ज़ब्त करने के औचित्य पर विचार प्रस्तुत किया. भाकपा नेताओं में से प्रत्येक के अपने अंतर्विरोधी विचार प्रस्तुत किए जाने के बाद आगामी समय की दूसरी बैठके आगे और पीछे के सत्र में समाहित कर ली गयीं जिसमें सोवियत प्रतिनिधिमंडल ने बहुत सारे मसलों पर सवाल खड़े कियें: पार्टी नेतृत्व में टिटोपंथी की कथित पैठ; कैसे भाकपा ने चीन के बारे में नेहरू की विदेश नीति के लिए अपने समर्थन के साथ हथियारबंद संघर्ष की अपनी आम दिशा को जोड़ा; दिसंबर १९५० की सभा में केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो के

पुनर्गठन का आधार जब पार्टी इतनी गहराई से अपने विचारों में विभाजित थी; भाकपा के पास अपना एक कार्यक्रम और संविधान था या नहीं; तेलंगाना और आंध्र में छापामार संघर्ष का तथ्यात्मक विवरण और छापामार सेनानियों के हाथों में हथियार के प्रकार; और, अंत में, सेना में पार्टी द्वारा किये गए राजनीतिक काम की हद. भाकपा नेताओं के विचार विमर्श और प्रतिक्रियाओं से उस समय के कम्युनिस्ट आंदोलन की स्थिति के बारे में एक अनोखी तस्वीर उभरती है.

सोवियत और भारतीय प्रतिनिधिमंडलों के बीच हुई दो प्रारंभिक बैठकों और उनेके लिए तैयार किये गए दस्तावेजों ने ९ फ़रवरी १९५१ को भारतीय प्रतिनिधिमंडल की जे. वी. स्टालिन के साथ हुई बैठक के लिए पृष्ठभूमि तैयार की. मास्को बैठकें भाकपा कार्यक्रम की तैयारी की प्रक्रिया शुरू की जो आधुनिक संशोधनवाद की शुरुआत तक भारतीय कम्युनिस्टों को एकजुट करने के लिए की गयी थीं.

विजय सिंह

उपस्थित:

कामरेड जी. एम. मलेंकोव, एम् अ. सुस्लोव, पी. ऍफ़. युदीन और वी. जी. ग्रिगोरियन.

भाकपा के के. स. के प्रतिनिधि महासचिव राजेश्वर राव, पोलित ब्यूरो के सदर्स्य कामरेड डांगे और कामरेड घोष और के.स. के सदर्स्य कामरेड पुन्नैया.

बहस में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों के परस्पर परिचय के बाद भाकपा के. स. ने उनके आने के उद्देश्य के बारे में बाते रखी.

कामरेड राव: हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें सोवियत संघ में आने का अवसर मिला है ताकि हम अन्तराष्टीय साम्यवाद के हरावल ए-यूसीपी (बी) से सीधे सुझाव ले सके. समाचार पत्र "फॉर ऐ लास्टिंग पीस, फॉर ऐ पीपल्स डेमोक्रेसी" में सम्पादकीय प्रकाशित होने के बाद और पेकिंग में एशिया के देशो के मजदूर संगठनों के सम्मेलन में लीउ शाओ ची के भाषण के बाद, हमारे बीच राजनैतिक दिशा को ले कर बहुत ही गंभीर मतभेद उभर कर सामने आये है. मतभेद ने ऐसी स्थिथि पैदा की है कि पार्टी का काम पूरी तरह ठप्प पड़ गया है. सभी लोग ए-यूसीपी (बी) से सहायता और मार्ग दर्शन की अपेक्षा कर रहे है. इन दिनों, भारत में बहुत से दल और संगठन उभर कर सामने आयें हैं, इनमें से प्रत्येक जनता को गोलबंद कर रहा है और जनता को अपनी तरफ खींच रहा है. हमारी पार्टी हतोत्साहित है जो कि एक गंभीर स्थिति पैदा कर रही है. हम सभी सहमत है कि हम अकेले अपने आंतरिक संकट का समाधान नहीं कर सकते. अगर हमें सहायता नहीं मिली तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी बिखर सकती है. समूची पार्टी दिशा निर्देश के लिए ए-यूसीपी (बी) की ओर देख रही है. मै चाहता हूँ कि दूसरे कामरेड्स भी बोले. मैंने सिर्फ अपना नजरिया रखा है.

कामरेड घोष : कामरेड राव ने जो कुछ कहा है, उसमे जोड़ने के लिए मेरे पास अतिरिक्त कुछ भी नहीं है. पार्टी में गंभीर मतभेद उभर कर सामने आये है, इसके बारे में मै बाद में चर्चा करूगा, लेकिन अभी मै निम्न बातें कहना चाहता हूँ: हमारे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बिना ए-यूसीपी (बी) की सहायता के हम पार्टी को आगे ले जाने में असमर्थ है, हम अंतराष्टीय कम्युनिस्ट आन्दोलन और इसके हरावल ए-यूसीपी (बी) से सहायता की अपेक्षा रखते है. मै कामरेड राव के

इस कथन से सहमत हूँ कि ए-यूसीपी (बी) द्वारा दिए गए सुझाव पूरी पार्टी को मान्य होगा.

कामरेड डांगे: ऐसा पहली बार नहीं है कि ए-यूसीपी (बी) हमे निर्देश और मार्गदर्शन दे रही है. सितम्बर १९४७ में ए-यूसीपी (बी) ने निर्देश दिए थे जब मै यहाँ था और जब कामरेड ज्ह्दानोव ने भारतीय प्रश्न पर मेरे विचारो को सुना था. यह सर्विदित है कि ए-यूसीपी (बी) हमेशा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ -साथ सभी पार्टियों के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति रही है.

शायद प्रश्न को विस्तार से व्याख्या करने की जरुरत नहीं है क्योंकि इसकी व्याख्या पहले ही भेजे गए दस्तावेज़ में की जा चुकी है. निसंदेह 'फॉर ऐ लास्टिंग पीस, फॉर ऐ पीपल्स डेमोक्रेसी' समाचार पत्र का सम्पादकीय हमारे मतभेदों का मुख्य आधार है. संभव है कि सम्पादकीय को समझने में हमसे कोई भूल हुई हो, इसलिए हमारा निवेदन है कि हमे सुझाव दिय जाएँ कि हम उस सम्पादकीय की व्याख्या किस तरह करे.

कामरेड पुन्नैया: पार्टी में सीधा विभाजन है. विघटन से बचने के लिए हमने समझौता किया है. दिसम्बर १९५० में के. स. की एक बैठक हुई थी जिसमे चर्चा हुई थी कि कैसे पार्टी की एकता ए-यूसीपी (बी) से सुझाव आने तक बरक़रार रखी जाये. सच्चाई यह है कि पार्टी पहले से ही विघटित है. प्रादेशिक इकाइयाँ स्वतंत्र रूप से काम कर रही है. केन्द्रीयता के साथ समझौता करना पडा है. अंतराष्टीय कम्युनिस्ट आंदोलन के हरावल ए-यूसीपी (बी) के प्रति पार्टी के सदस्यों का अटूट विश्वाश है. और देश के सभी बाम ताकतों का अंतर्राष्टीय कम्युनिस्ट आन्दोलन-

इनफार्मेशनब्यूरो के नेतृत्व पर भी विश्वास है. हमे पार्टी को एक करने की जरुरत है क्योंकि यह हमे नयी ताकत देगी.

कामरेड राव: कुछ ऐसा हुआ है कि हमलोगों ने अपने मतभेदों के बारे में दस्तवेज़ लिखने की आदत विकसित कर ली है जो सैकड़ो पन्नो में होते हैं, मगर ये पता नहीं है कि ये कैसे शुरू हुई. बेहतर होता कि हम अपने मतभेदों को लिख डालते, केवल सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की ही चर्चा करते, इसलिए भी , क्योंकि मै अंग्रेजी में बहुत धाराप्रवाह नहीं हूँ और बोलते समय बड़ी कठिनाई से अपने विचारो को अभिव्यक्त कर पाता हूँ. इसके अलावे मै अप्रयाप्त रूप से अपने विचारों में खोया रहता हूँ और मुझे अपने विचारो को रखने के पहले उस पर सोचने की जरुरत होती है. इसके लिए मै कुछ और समय लेना चाहुगां. बहुत सारे - राजनैतिक और सांगठनिक दोनों - सवालों पर हम सुझाव और मार्गदर्शन चाहते है और हम आपकी सहायता से दो प्रस्ताव का मसौदा तैयार करना चाहते है, जिसे हम वापस ले जाये गे, फिर उसपर चर्चा करेगे और सम्मेलन में उसे स्वीकृत करेगे.

परिचर्चा की प्रक्रिया के बारे में विचारों के आदान- प्रदान के बाद भारतीय कामरेडों ने अपने विचार अभिव्यक्त करने की इच्छा जाहिर की.

कामरेड घोष - पार्टी के द्वितीय कांग्रेस के तुरंत बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था और ५ माह पहले ही मुझे जेल से छोड़ा गया. जो कुछ भी हुआ उसका सम्पूर्ण और प्रत्यक्ष जानकारी मेरे पास नहीं है. प्रत्यक्षत: पार्टी के अन्दर एक खतरनाक सांगठनिक विफलता सामने आई है और स्थिति ऐसी है कि हममे से कोई भी पार्टी के अन्दर वास्तविक स्थिति के बारे में नहीं जानता. पार्टी के खिलाफ दमन इतना तेज है कि पार्टी की प्रांतीय इकाइयों के बारे में किसी को

कोई जानकारी नहीं है.

मेरा मत क्या है ? द्वितीय कांग्रेस के पहले पार्टी की नीति सुधारवादी थी. द्वितीय कांग्रेस में इसकी तीव्र आलोचना हुई. कांग्रेस द्वारा स्वीकृत राजनैतिक मान्यताएं मोटे तौर पर सही थीं, लेकिन कुछ गलतिया भी थी, ख़ास तौर से, हमारी क्रांति की अवस्था के बारे में वहाँ कोई उल्लेख नहीं किया गया था और इस तरह पेश किया गया था मानो हमारी क्रांति दो क्रांतियो -जनवादी और समाजवादी - के विशेषताओं को समाहित किये हुए हो. यह सब युगोस्लाविया से आये प्रतिनिधियों के प्रभाव के कारण था जो कांग्रेस में उपस्थित थे और जिन्होंने इस दृष्टिकोण को हमारे ऊपर थोपने की कोशिस की.

कांग्रेस ने केंद्रीय समिति का चुनाव किया लेकिन मई १९५० तक के. स. की एक बार भी बैठक नहीं हुई. महासचिव कामरेड रणदिवे ने एक चरम - बामपंथी कट्टरवादी नीति चलाया जो "राजनैतिक मान्यता" की दिशा से एक भटकाव था. दिसम्बर १९४८ में उन्होंने एक दस्तावेज़ तैयार किया था जो पोलित ब्यूरो द्वारा स्वीकृत किया गया था. एक चरम -बामपंथी कट्टरवादी नीति इन दस्तावेजों में प्रतिपादित की गयी थी. मै यंहा उनके बारे में नहीं बोलूगां, ये सर्वविदित है.

'"फॉर ऐ लास्टिंग पीस, फॉर ऐ पीपल्स डेमोक्रेसी' समाचार पत्र में सम्पादकीय प्रकाशित होने तक इस राजनैतिक दिशा को लागू किया गया. इसके बाद कामरेडों ने खुलकर रणदिवे के इस राजनैतिक दिशा की आलोचना करना शुरू कर दिया. मई १९५० में, कांग्रेस के बाद, के. स. की पहली बैठक हुई जिसमे ३१ में से के. स. के १९ सदर्स्य उपस्थित थे.

के. स. ने पार्टी कार्यकर्ताओ के लिए एक पत्र स्वीकृत किया जिसमे पार्टी की नयी राजनीतिक दिशा प्रतिपादित की गयी. उसमे उल्लेख किया गया था कि यह

राजनैतिक दिशा 'फॉर ऐ लास्टिंग पीस, फॉर ऐ पीपल्स डेमोक्रेसी' समाचार पत्र के सम्पादकीय और पेकिंग में आयोजित मजदूर संगठनों के सम्मेलन के घोषणा पत्र में वर्णित सिद्धांतो के आधार पर तैयार गयी है.

पार्टी के इस नयी दिशा के प्रतिपादित होने के बाद मतभेद ख़त्म नहीं हुए बल्कि वे और भी तीव्र हो गए. दिसम्बर १९५० में द्वितीय कांग्रेस द्वारा निर्वाचित के. स. की बैठक हुई लेकिन यह बैठक भी मतभेदों को ख़त्म करने में नाकामयाब रही. और तब सभी राजनैतिक प्रवृत्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक एकताबद्ध के. स. और पोलितब्यूरो के निर्माण करने का हमने निर्णय लिया. विचारो की एकता की दृष्टि से हमारा के. स. और पोलितब्यूरो एकताबद्ध नहीं कहा जा सकता. पार्टी को टूटने से बचाने के लिए हमें यह कदम उठाना पड़ा.

मेरी राय में, द्वितीय कांग्रेस के बाद पार्टी की गलतियाँ दो तरह की थी. पार्टी ने क्रांति की अवस्था का निर्धारण करने में गलती की और गलत तरीके से माना कि हमारी क्रांति दो क्रांतियों का एक संयोजन होगा.

दूसरे, देश में स्थिति का मूल्यांकन करते हुए पार्टी ने गलती की, स्थिति की परिपक्वता और जनता के बीच क्रांतिकारी जोश का अतिरंजन किया और यह सोचकर जोखिम भरे नारे जारी किये कि पार्टी उन्हें व्यवहार में लागू करेगी और जनता उनका अनुसरण करेगी. ये दो गलतिया थी.

जब जनता का राष्ट्रीय कांग्रेस से मोहभंग होना शुरू हुआ, पार्टी ठोस नारे देने में विफल रही और इसके बजाय विद्रोह करने और सत्ता हथियाने के नारे के साथ आगे बढ़ी. परिणाम के रूप में, हालांकि, इन तीन वर्षो में राष्टीय कांग्रेस जनता से दूर होती रही, हम नहीं कह सकते के कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी ताकत

कांग्रेस की विफलता के चलते बढ़ाया है. उलटे, दूसरी पार्टियाँ, कहा जाये तो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की विफलता से फायदा मिला है.

पार्टी <u>समस्त</u> जनता पर अपने प्रभाव का विस्तार नहीं कर सकी. जनता को कदम-दर-कदम आगे ले जाने के लिए सरकारी बजट बढाने और शांति आन्दोलन जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को नहीं उठा सकी.

अगस्त में भारत सरकार के प्रतिनिधि या शायद खुद नेहरु ने आम चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर आयोजित करने की घोषणा की. अभी तक 12-13% लोग वोट कर सकते थे. हर पार्टी अपने खुद के कार्यक्रम के साथ आई जिसने खूब हलचल पैदा किया. एक मात्र हमारी पार्टी ही ऐसी थी जिसके पास कहने को कुछ नहीं था. उस समय अगर यह एक ठोस कार्यक्रम के साथ आती और चुनाव कराने की मांग करती, इसे सफलता मिलती और पार्टी के प्रभाव को भी बढ़ा पाती, लेकिन पार्टी चुप रही. चुनाव एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया था. अगर उस समय पार्टी आगे आती, वह सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से को निर्देशित करने में सक्षम हो पाती.

पार्टी दस्तावेज़ कहता है कि भारत गृह युद्ध के बीचो- बीच है, और एक जगह यह कहता है कि जो इस गृह युद्ध को होते हुए नहीं देख सकते, वे परिस्थिति को समझ नहीं पाते. मेरे अनुसार यह परिस्थिति का एक निरा बढ़ा-चढ़ा आकलन है. जहाँतक मै समझता हूँ, गृह युद्ध की स्थिति तभी होती है जब हथियारबंद जनता का एक बड़े क्षेत्र पर सरकार की सेना के साथ हथियारबंद संघर्ष हो. ठीक, इसी बढे-चढ़े आकलन के आधार पर जनता की ठोस मांगो की उपेक्षा की गयी.

हम लोग शांति आन्दोलन का निर्माण करने में असफल रहे. क्यों? क्या इसलिए कि अंग्रेजी और अमेरकी साम्राज्यवाद के खिलाफ जनता के बीच प्रयाप्त घृणा नहीं थी? गलत. यंहा तक कि कांग्रेस का अखबार भी कोरिया में अमेरिकी हमले के खिलाफ था. कोरियाई जनता के लिए हमारी सहानुभूति सर्वविदीत है.

कोरिया के सवाल पर नेहरु ने एक वक्तव्य दिया था. हमारी पार्टी को छोड़ कर सभी अखबारों ने प्रतिक्रिया दी. यह दर्शाता है कि कोरियाई जनता के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने में हम असमर्थ रहे और इस तरह हम जनता से अलग-थलग हो गए.

एक और महत्वपूर्ण टिपण्णी. हमारी के. स, औधोगिक मजदूरों को प्रयाप्त महत्त्व नहीं देती. निसंदेह, भारत एक उपनिवेश है, लेकिन सापेक्षिक रूप से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले विशाल मजदूरवर्ग के साथ एक विकसित उपनिवेश है. इसलिए न सिर्फ कृषि क्षेत्र में बल्कि देश के जीवन में मजदूर वर्ग अहम् भूमिका पेश कर सकता है. इसके अलावे यें साम्राज्यवादियों और इसके समर्थकों के खिलाफ अपना संघर्ष चला रहे है.

दस्तावेज़ चीनी क्रांति का अन्धानुकरण करने के प्रयास को प्रतिम्बित करता है. कामरेड मजदूर वर्ग की महान क्षमता को नहीं देख पाते है. मेरे विचार में हमारे मतभेद मुख्यरूप से हथियारबंद संघर्ष और और जनवादी संयुक्त मोर्चा के सवालों पर है. अपने दस्तावेज़ में हमने अपने मतभेद के सार को रखने का प्रयास किया है. बहस फिर इस प्रश्न पर आ कर रूक जाता है कि हमारे देश में किस हद तक क्रन्तिकारी परिस्थिति परिपक्व हुई है. अलग अलग स्थितियों में संघर्ष के विभिन्न रूप प्रभुत्व हासिल करते है. के. स. की मई में हुई बैठक में स्वीकार किया गया था कि हथियारबंद संघर्ष संघर्ष का मुख्य रूप है और सभी रूपों को

सहायक होना चाहिए। मै समझता हूँ कि आमतौर पर उपनिवेशों के लिए यह सही है, परन्तु मै यह भी समझता हूँ कि इस बात के लिए अभी स्थितियां परिपक्व नहीं है. ठोस स्थितियों का आकलन किये बिना इस दावे को औपचारिक रूप से स्वीकृत करना पार्टी के लिए गलत होगा।

मै समझता हूँ की दमनचक्र और हमारे मतभेदों के चलते पार्टी काफी हद तक कमजोर हो गयी है. मजदूरों के बीच पार्टी का प्रभाव कम हुआ है. कपड़ा मजदूरों का पिछला हड़ताल समाजवादियों के नेतृत्व में हुआ था.

मेरे विचार में भाकपा के. स. का मुख्य कार्य अंग्रेजी साम्राज्यवाद, सामंतवाद और उसके सहयोगी पूंजीपति वर्ग के खिलाफ भारतीय जनता की व्यापक संभव एकता स्थापित करना है. इस जनवादी मोर्चा को एक युद्ध विरोधी मोर्चा भी होना होगा. वर्तमान में हथियारबंद संघर्ष, संघर्ष का मुख्य रूप नहीं हो सकता क्योकि पार्टी ने जनता के बीच अपना प्रभाव खो दिया है. हालाकि, जंहा हथियारबंद संघर्ष के लिए परिस्थितियां परिपक्व है वंहा हमे संघर्ष जारी रखने की जरुरत है लेकिन उसे आत्मरक्षा के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए. उस तरह के हथियारबंद संघर्ष को जमीन के लिए किसानो के संघर्ष का हिस्सा होना होगा. परिणामस्वरूप, जंहा इस तरह की स्थितिया बनती है, हमे हथियार बंद संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना चाहिए.

कामरेड डांगे - मै कुछ अतिरिक्त टिपण्णी करना चाहता हूँ. चीनी पथ की व्याख्या किस तरह की जाए, मतभेद इसी बिंदु के इर्द-गिर्द थे. पार्टी की बदलती हुई दिशा के बारे में मै कुछ नहीं कहना चाहता. दूसरी पार्टियों की सहायता के बिना हमारी पार्टी कभी कोई अपनी दिशा तय नहीं कर सकी. जब भी हमारी पार्टी की दिशा गलत थी, दूसरी विरादराना पार्टियों ने इसे सही करने में हमारी सहायता

की. द्वितीय कांग्रेस में आन्ध्र के कामरेड के भाषण के बाद मतभेद शुरू हो गए. भारत में चीनी पथ के अनुसरण को लेकर बहस जारी था. खासतौर से, लीउ शाव ची द्वारा पेकिंग सम्मलेन में हथियारबंद संघर्ष को मुख्य संघर्ष का रूप प्रस्तावित करने के बाद, कुछ लोग सोचते थे कि लोगो को चीनी पथ का अनुसरण करना चाहिए. बहुत से लोग मानते थे कि हम पहले ही चीनी पथ का अनुसरण कर रहे है और सभी मामलो में हथियारबंद संघर्ष को अहमियत दी जाती थी और संघर्ष के सभी दूसरे रूपों की उपेक्षा की जाती थी (हड़ताले, बैठकें, शांति के लिए प्रचार आदि). सभी मामलो में कहा जाता था: हथियार उठाओ! संघर्ष के सभी रूपों के बीच समन्वय अनुपस्थित था। इस बात को नजरअंदाज किया गया था कि जनवादी मोर्चा में, जिसका सारतत्व जमीन के लिए किसान संघर्ष होता है, हथियार बंद संघर्ष लाजिमी होता है. लेकिन इसे संघर्ष के अन्य रूपों के साथ सामंजस्य में होना चाहिए. इस पक्ष की नजरंदाजगी ही वह चीज थी जिसकी आलोचना मैंने चरम-बामपंथी कट्टरवादी राजनीति के रूप में की थी.

दूसरा मतभेद चीनी पथ की व्याख्या को लेकर था. संघर्ष के अर्ध-कानूनी और कानूनी तरीको का छापामार युद्ध के साथ तालमेल कैसे किया जाये? उस तरह के संघर्ष के रूपों के बीच तालमेल करने का अनुभव मेरे पास नहीं है. केंद्रीय समिति के निर्देशानुसार, छोटे से हथियारबंद इकाइयों को जमींदारों के खिलाफ लड़ने का आदेश मिला था जिसे मुश्किल से छापामार युद्ध माना जा सकता है. इस तरह के आदेशों को शहरों तक बढ़ा दिया गया था जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारियों को मार देने का आदेश मजदूरों को दिए गए थें.

१९५० के पत्रों में से एक में यह कहा गया था कि भारत में क्रांति की शुरुआत अब बस कुछ ही दिनों की बात है. यह दुस्साहसवाद है और चीनी पथ की

इस तरह की व्याख्या के विरोध में मै बोलता हूँ. चीनी पथ की व्याख्या करने का प्रश्न एक कठिन प्रश्न है और मै इस प्रश्न को स्पष्ट करना चाहता हूँ.

कामरेड घोष: कामरेड डांगे चाहते है कि चीनी पथ के प्रश्न का विस्तार से व्याख्या किया जाना चाहिए. छापामार युद्ध के बारे में मै कुछ स्पष्ट करना चाहुगा.

आंध्र में जमींदारों के खिलाफ छापामार युद्ध चलाया जा रहा है. छापामार इकाइयाँ जमींदारो को मार देते हैं और उनका सबकुछ ले लेते हैं. क्या इस तरह का संघर्ष प्रदेशों को मुक्ति की तरफ ले जाता है और छापामार युद्ध को व्यक्तिगत जमींदार के खिलाफ आतंकवादी कार्यवाही में विकृत होने से कैसे रोका जाये? छापामार संघर्ष को प्रतिक्रियावादी सरकार की सैन्य-शक्ति के खिलाफ एक सच्चे संघर्ष में कैसे तब्दील किया जाये?

अगला प्रश्न नेहरु सरकार के बारे में है. इसकी नीति का आकलन कैसे किया जाये? कैसे इसे शांति के लिए संघर्ष के साथ तालमेल बैठाया जाये ? ये कुछ प्रश्न है जिनपर हमें प्रतिक्रिया की अपेक्षा है.

कामरेड पुन्नैया: जैसा कि हमे सचिव ने बताया, अंग्रेजी का अप्रयाप्त ज्ञान हमारे लिए एक गंभीर समस्या है. कामरेड डांगे और घोष ने बॉम्बे प्रदेश में काम किया है जंहा लोग प्राय: अंग्रेजी में लिखते और बोलते है. हम लोगो ने जिस प्रदेश में काम किया है वहां अंग्रेजी का चलन नहीं है. इस लिए अंग्रेजी के अप्रयाप्त जानकारी के लिए मै क्षमा प्रार्थी हूँ. संभवतः हम हमेशा अपने विचारो को सही ढंग से व्यक्त करने में सक्षम नहीं होगें.

अगर हम कामरेड डांगे और घोष के मतों पर अपनी टिपण्णी दे तो यह उन्ही बातो का दोहराना होगा जो हमारे दस्तावेज़ में पहले ही कहा गया है. मै मुश्किल में हूँ, मुझे नहीं पता बहुत सारे प्रश्नों की कैसे व्याख्या की जाये.

चीनी पथ के प्रश्न और दूसरे सैद्धांतिक प्रश्नों पर आने के पहले मै चाहता हूँ की हम कुछ तथ्यों का स्मरण करें.

द्वितीय कांग्रेस के समय ३००० गाँव वाले क्षेत्र में हम हथियारबंद संघर्ष चला रहें थें. संघर्ष दस महीनो तक चलता रहा था. महासचिव घोष और उनकी सुधारवादी कार्यनीति 'सतर्क रहें और पीछे हटने के लिए एक बचाव का रास्ता छोड़ दें" के द्वारा यह संघर्ष ठप्प कर दिया गया. तेलंगाना में संघर्ष को के. स. के निर्देश के खिलाफ जा कर जारी रखना पड़ा, जिनके प्रतिनिधियों ने संघर्ष बंद करने की मांग की थी.

लेकिन परिस्थिति ने हमें आगे बढ़ने को मजबूर किया. पार्टी के द्वितीय कांग्रेस के समय तेलंगाना में कृषि क्रांति के सवाल पर प्रयाप्त ध्यान नहीं दिया गया. आंध्र और तेलंगाना के प्रतिनिधिमंडल (१८० व्यक्तियों से ज्यादा) को तेलंगाना आन्दोलन के पक्ष में कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच प्रचार करना पड़ा. मुख्य वक्ता कामरेड रणदिवे ने तेलंगाना और आंध्र में चल रहे संघर्ष के सवाल की उपेक्षा करने का हर प्रयास किया. हमारे प्रतिनिधि कांग्रेस में एक ठोस प्रस्ताव आगे बढ़ने में कामयाब हुएं और इस तरह इस समस्या के प्रति सभी प्रतिनिधियों का ध्यान खींच सकें.

बहुत सारी समस्याएं जो कांग्रेस के पहले स्पष्ट नहीं थी, कांग्रेस के बाद भी वे स्पष्ट नहीं हुए है. वैसे प्रश्न जैसे वर्ग - शक्तियों के संतुलन, क्रांति के चरण और भविष्य, वर्गों की एकता, हथियारबंद संघर्ष आदि के प्रश्न उभर कर आयें और हम उनपर चर्चा कर सकते थे. अखिल भारतीय सवालों पर हमने एक मसौदा भाषण रखा और इस पर पार्टी इकाइयों में बहस करने की अनुमति देने का निवेदन के. स. से किया. के. स. नहीं बैठी. पोलित ब्यूरो ने चर्चा की और मसौदा

को ख़ारिज कर दिया. हम ने फिर मांग की कि हमारे मसौदा पर बहस की जाये. तब पोलित ब्यूरो ने एक दस्तावेज़ "रणनिति और कार्यनीति पर" जारी किया, जो हमारे दस्तावेज़ का जबाब था.

हमने सभी बहसें बंद कर दी. लेकिन, प्रदेशो में हमने हथियारबंद संघर्ष एक रक्षात्मक संघर्ष के रूप में जारी रखा. उसके बाद एशिया के मजदुर संगठनों का पेकिंग में सम्मलेन हुआ और "एक पीपुल्स लोकतंत्र के लिए, एक स्थायी शांति के लिए" अखबार में सम्पादकीये प्रकाशित हुआ.

इसके बाद पार्टी के भीतर अवस्थित मतभेद और भी तीव्रता से उभर कर सामने आयें. यें वें तथ्य है जिनकी तरफ मै ध्यान आकर्षित करना चाहता था.

मई १९५० में के. स. की पूर्ण सभा हुई. के. स. में ३१ में से केवल १९ सदर्स्य बचे थे. बाकी सभी जेल में थे, दो अनैतिक व्यवहार के आरोप के चलते हटा दिए गए थे. पहली बहस जो हुई वो आश्चर्य से भरी थी. वे कामरेड जो पहले त्रोत्स्किपंथी अवस्थिति, जैसे कि एक स्तरिये क्रांति चलाने, का बचाव किया था, अब वे कहना शुरू किये कि अब हमें सबकुछ फिर से शुरू करना चाहिए. पहले वे कहते थे कि भारत में साम्राज्यवाद नहीं है और भारतीय पूंजीपति प्रतिक्रियावादी ताकतों को नेतृत्व दे रहा है. अब ये कामरेड कहते है कि कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है और कि भारतीय पूंजीपति साम्राज्यवाद का पीछलग्गू है. द्वितीय कांग्रेस में संसोधनवाद से संकीर्णतावाद की तरफ झुकाव हुआ है. पोलित ब्यूरो और के. स. के सभी सदर्स्य पुरानी अवस्थिति के विरोध में हो गये हैं. साथ ही, जोशी ने अपनी विवरणिका 'दृश्य' प्रकाशित किया जहाँ उन्होंने अपनी लगातार सुधारवादी दिशा का बचाव किया जिसे पूरी तरह से द्वितीय कांग्रेस ने ख़ारिज कर दिया था. जोशी तेलंगाना में हथियारबंद संघर्ष के खिलाफ तर्क करते है और वह हमे

नेहरु सरकार को समर्थन देने को कहते है और जब भारतीय फ़ौज हैदराबाद में प्रवेश करती है तो तेलंगाना संघर्ष छोड़ देने को प्रस्तावित करते है. पार्टी के भीतर ऐसे कामरेड थे जो जोशी के विचारो से इत्तिफाक रखते थे. दिसम्बर की सभा में के. स. के कुछ सदस्य्यों ने जोशी को समर्थन दिया था.

इन परिस्थितियों में पार्टी की नयी दिशा तैयार की गयी थी. हथियारबंद संघर्ष को मुख्य संघर्ष के रूप में इस उद्देश्य से आगे रखा गया था ताकि दिखाया जा सके कि पार्टी को मौजूदा रिज़र्व का इस्तेमाल करने की जरुरत है.

जब कामरेड डांगे घोषणा करते है कि के.स. ने कहा है ''राइफल उठाओ और गोली दागो', यह पार्टी के खिलाफ एक झूठी निन्दा है. कई प्रदेशो में संघर्ष के कई रूप मौजूद है. मुद्दे का अतिसरलीकरण करने का मतलब है - प्रस्ताव को रोकना. के. स. ने राजनैतिक दिशा की स्वीकृति तब दी थी जब प्रदेशों ने, जंहा हथियारबंद संघर्ष जारी था, अपने विस्तृत दस्तावेजों को पेश किया, जिनमे यह दिखाया गया था कि जमींदारों की जमीन किस तरह बाटीं गयी थी, हमारी सत्ता किस तरह संगठित की गई थी, आदि. केवल इन दस्तावेजों की पूरी जांच के बाद ही के. स. ने अपना निर्णय लिया था.

इस प्रश्न पर कि हमने शान्ति आन्दोलन का निर्माण नहीं किया या हमने इसमें अपनी भागीदारी नहीं की, मै बाद में आऊंगा. के. स. ने अपना काम जून में शुरू किया, कार्यकर्ताओ की कमी थी क्योकि केवल ९ लोग ही के. स. में निर्वाचित हुए थे जिसमे से ४ को प्रदेश छोड़ना पड़ा था. बाकी सदस्र्य हतोत्साहित थे और प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने की स्थिति में नहीं थे. जेल से छुटें कामरेड ६ माह तक के. स. में उपस्थित नहीं हुए. उन परिस्थितियों में कैसे मांग की जा सकती है कि के. स. यह या वह करे. के. स. के ऊपर यह आरोप लगाना

सही नहीं है कि इसने शांति आन्दोलन संगठित नहीं किया और चुनाव प्रचार के लिए आह्वान नहीं किया.

हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले कहते है कि हम हथियारबंद संघर्ष के विचारो में इतने बह गए की हमने संघर्ष के दूसरे रूपों को नुकसान पहुँचाया. मै समझ नहीं पाता कि लोग हम पर चुनाव वहिष्कार करने का आरोप क्यों लगाते है, क्योकि हैदरावाद में, जंहा हथियारबंद संघर्ष जारी था, हमने चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया लेकिन चुनाव ख़ारिज हो गया था.

मेरे विचार में हमें बहुत सारे प्रश्नों पर एकमत होने की जरुरत है. संयुक्त राष्टीय मोर्चा का कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन इस मोर्चे के स्वरुप के बारे में, चीनी पथ के बारे में कई प्रश्न हैं. पार्टी नेतृत्व में सभी लोग चीनी पथ के बारे में "एक पीपुल्स लोकतंत्र के लिए, एक स्थायी शांति के लिए" पत्रिका के सम्पादकीय से सहमत है. कामरेड डांगे और कामरेड घोष कहते है कि हम चीनी पथ को यथावत लागू करना चाहते है, मगर हमारा मानना है कि चीनी पथ के बारे में उनकी समझ यांत्रिक है. वे कहते है कि भारत आर्थिक रूप से एक विकसित देश है. यह साबित करने के लिए कि भारत चीन से ज्यादा विकसित देश है, वे इस पक्ष पर ज्यादा जोर देते है और कहते है कि चीन में सेना थी जब कि भारत में नहीं है और स्तालिन का संदर्भ देते है जिसके अनुसार चीनी पथ भारत में लागू नहीं हो सकता.

नेहरु के विदेश नीति के बारे में. हम इस नीति का पर्दाफास कैसे करते है? कामरेड घोष कहते है कि सिवाए हमारी पार्टी के सभी पार्टियों ने नेहरु की नीतियों पर अपना वक्तव्य दिया है. हम नहीं जानते कि धोखे से भरी नेहरु की नीति का पर्दाफास कैसे करे.

मुझे यह स्पष्ट है कि अपनी चर्चा के परिणामस्वरुप हमे ऐसे दस्तावेज़ तैयार करने की जरुरत है जो हमारे बीच के सभी गुटीय संघर्ष को समाप्त कर दे.

अतीत में हमारी पार्टी ने कई गलतियां की और इसने पार्टी एकता को कमजोर किया. यह भी जरुरी है कि आप हमारी गलतियों पर अपनी आलोचना करे क्योकि यह हमे सही करने और पार्टी को एकताबद्ध करने में सहायता करेगा.

कामरेड राव: कामरेड, शुरू में मै कामरेड डांगे और घोष के कथन पर कुछ टिपण्णी करना चाहुगां. उन्होंने एक सूत्र “बंदूख उठाओ और गोली दागो” में ढाल कर हमारी दिशा को सरलीकृत किया है. यह एक सरलीकरण है जो कहीं से भी हमारे ध्येय की सहायता नहीं करता. मै बाद में प्रकाश डालूगा कि डांगे एक अवसरवादी है. मजदूरवर्ग की भूमिका नहीं समझने का आरोप वे हम पर लगते है. मै इस पर बाद में आऊंगा कि बहुत सारे प्रश्न पहले क्यों नहीं उठाये गएँ. हमने लगभग १०० पेज के दस्तावेज़ में अपनी बातें रखीं हैं. चुनाव प्रचार का प्रश्न भी यहाँ रखा गया है.

मैं इस केंद्रीय प्रश्न पर ध्यान केन्द्रित करूगां कि हथियारबंद संघर्ष ही संघर्ष का मुख्य रूप है. मै बताऊंगा कि कैसे हम इस प्रश्न को समझते हैं. जब यह घोषित किया जाता है कि हम हर जगह हथियारबंद संघर्ष संचालन करने की जरुरत की वकालत करते है, जैसा कि कहा जा रहा है, ये हमारे विचार नहीं है. हमने हथियारबंद संघर्ष दो क्षेत्रों - तेलंगाना और आंध्र में चलाया और अन्य क्षेत्रों में हमने संघर्ष के दूसरे रूपों को लागू किया. तेलंगाना के ८ जिलों में से सिर्फ दो जिलों में हथियारबंद संघर्ष हमने चलाया. आंध्र के ११ जिलों में से सिर्फ ४ जिलों में ही चलाया गया. इसी तरह हमने हथियारबंद संघर्ष के दायरे का विस्तार किया है. हथियारबंद संघर्ष से हम क्या समझते है? वर्तमान में आप कहीं भी चाहे संघर्ष

के किसी भी रूप से शुरू करे, आप एक फासीवादी प्रकार के दमन का सामना करेंगे. इस लिए हम इस प्रश्न को आगे रखते है कि संघर्ष करने के अपने अधिकार की रक्षा जनता को अपने हाथो में हथियार ले कर करनी चाहिए. इसी लिए हमे जनता से सीधे कहना चाहिए कि बिना हथियारबंद संघर्ष के वे अपनी मांगो के लिए आवाज उठाने के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते. हमारे विरोधी अब कहते है कि केवल कुछ ही क्षेत्रों में हथियारबंद संघर्ष का मुख्य रूप हो सकता है, लेकिन लोगो के सामने वे इस तथ्य को कहने को तैयार नहीं है कि बिना हथियारबंद संघर्ष के वे खुद की रक्षा नहीं कर सकते.

इस प्रश्न पर तीन प्रवृतियाँ है : हम यानि के. स. दूसरी - जोशी. हालाकिं वह पार्टी में नहीं है तो भी यह प्रवृति पार्टी में मौजूद है. तीसरी प्रवृति कामरेड घोष द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है. मुझे नहीं मालूम डांगे की अवस्थिति क्या है. क्योंकि उन्होंने बार बार अपनी अवस्थिति बदला है, उन्हें ही तय करने दे कि वे अपने आप को कहाँ खड़ा पाते है. जेल से छुटने के बाद उन्होंने एक घोषणा की थी जो मूलतः हमारे दृष्टिकोण के बहुत करीब था, बाद में उन्होंने दूसरा, पूरी तरह उल्टा वक्तव्य प्रकाशित कराया. कामरेड घोष द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेज़ में बहुत सारे अंतर्विरोध है. इस तरह तीन प्रवृतियाँ है - हम, जोशी और घोष.

क्या हमे रणदिवे की अवस्थिति के बारे में बोलना चाहिए? “फॉर ए लास्टिंग पीस, फॉर ए पीपल्स डेमोक्रेसी” में सम्पादकीय प्रकाशित होने के बाद अपनी अवस्थिति पर अडिग रहना वे जारी रखे और बाद में पूरी तरह से एक विपरीत दिशा में कूद पड़े. उन्होंने घोषणा की कि वे के. स. की अवस्थिति का समर्थन करते है लेकिन मै पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूँ कि वे ऐसा करते है.

जनता की चेतना के स्तर की स्थिति के बारे में हमारा आकलन क्या है ? जैसा कि हमने अपने दस्तावेज़ में इंगित किया है, देश के राजनैतिक जीवन में अहम् भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी जनता के बीच व्यापक प्रभाव रखती है, लेकिन १९४७ से इसकी पकड़ कम हो रही है और जोशी के नेतृत्व वाले के. स. का उस जनता से, जिसने कांग्रेस के प्रतिक्रियावादी चरित्र को समझना शुरू कर दिया है, जो कुछ भी कहना है वह यही है कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन करना जरुरी है. कांग्रेस की गद्दारी को समझने वाले आंध्र के ७५ % खेतिहर मजदूर, जिसमें बहुतयात "अछुत" है, हमें कहते हैं "यदि आप हमे स्वीकार नहीं करेगे तो कौन करे गा?"

द्वितीय कांग्रेस के पहले हमने सभी ताकतों - पटेल और अन्य के नेतृत्व वाले छोटे से गुट को छोड़ कर कांग्रेस पार्टी से ले कर कम्युनिस्ट तक- को संयुक्त मोर्चा में आने का आह्वान किया था. द्वितीय कांग्रेस के बाद हम कहते रहे है कि हालांकि रणदिवे विद्रोह करने का आह्वान करते है, वास्तविकता में कई क्षेत्रो में जंहा आम जनता हथियारबंद प्रतिरोध के लिए तैयार थी, वे हमे बाधा पहुचाते रहे है.

युद्ध के समय हमने खेतिहर मजदूरों को संगठित करने से इंकार किया क्योकि हमे किसान एकता के भंग होने का भय था.

जब गांधी की हत्या हुई, हत्या को बढ़ावा देने वाले संगठनो और अन्य अंध-राष्टवादी संगठनों के बीच झरपें भड़क उठी. सरकार ने इसे तेलंगाना और आन्ध्र में किसान आन्दोलन का खात्मा करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया.

द्वितीय कांग्रेस में हमारे प्रतिनिधिमंडल गैर-कानूनी तरीके से आये. आन्ध्र पार्टी संगठन में चीनी पथ और हथियारबंद संघर्ष आदि पर बहस जारी थी.

आन्ध्र के प्रादेशिक समिति द्वारा प्रस्तुत एक मसौदा दतावेज़ के जबाव में एक त्रोत्स्कीपंथी दस्तावेज़ 'रणनीति और कार्यनीति पर' सामने लाया गया था.

केरल प्रदेश में भी किसान आन्दोलन चल रहा था. के. स. इस आन्दोलन के भी समर्थन में यह कहते हुए नहीं आई कि "पहले एक जनवादी आन्दोलन तैयार करे और केवल तभी हथियारबंद प्रतिरोध संगठित करना शुरू करे." ऐसे कई उदाहरण हैं.

शहरों में हथियार के प्रयोग के बारे में बहुत कुछ अखबारों में लिखा गया है लेकिन वे सच नहीं हैं. कई जगहों पर हथियार उपलब्ध ही नहीं है. बंगाल में जंहा हथियार उपलब्ध था, रणदिवे ने उसे लोगो के बीच से हटा लिया. यह कहना गलत होगा कि रणदिवे ने शहरों में हथियारबंद संघर्ष संगठित किया. उन्होंने आतंकवाद को प्रोत्साहित किया जिसमे केवल एक पुलिसवाला मारा गया था.

हमारा दावा है कि हमारा आन्दोलन हथियारबंद संघर्ष में बदलने के कगार पर था. बंगाल के १९ इलाकें किसान आन्दोलन के प्रभाव में थें. लेकिन पुलिस से छीने गए हथियार वापस कर दिए गए थें.

अतीत में पार्टी नेतृत्व हथियारबंद संघर्ष के प्रश्न से बचता रहा है . कांग्रेस ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है. जनता दूसरी पार्टियों की ओर देख रही है और हम इस स्थिति का फायदा नहीं उठा पाए है. हमने एक आम हड़ताल का आह्वान किया था और हमें किसी ने समर्थन नहीं किया और उन जगहों पर जंहा किसान हथियारबंद संघर्ष की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें ऐसा करने से हतोत्साहित किया.

जनता की बहुतयात कांग्रेस से दूर जा रही है जो अब केवल हथियारबंद ताकतों पर ही भरोसा कर सकती है. निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के पास दूसरे

साधन है, लेकिन दमन चक्र का फासीवादी रूप ही वह मुख्य तरीका है जिसका हम सामना करते है.

यद्धपि कि हमने वामपंथी गुटीय कार्यनीति लागू की थी जिसने हमारे प्रभाव को बहुत कम किया, लोग तब भी हमारी पार्टी को नेतृत्व के लिए देख रहे हैं. हमारी पार्टी एक बड़ी ताकत है और कुछ प्रदेशों में पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है. अगर हम सही कार्यनीति अपनाये तो कांग्रेस पार्टी से दूर जा रही विशाल आबादी को अपने तरफ खींच सकते है. हम निष्क्रिय नहीं रह सकते, हमे कुछ करना है और तेजी से कार्य करना है.

जहाँ तक सरकार की नीति के मूल्यांकन का प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि सरकार के प्रगतिशील प्रकृति के बारे में बाते करना संभव है जिसे हमारे द्वारा प्रतिक्रियावादी घोषित किया गया था.

बहस जारी है (6 फरवरी)

कामरेड डांगे : हमारा देश कृषि क्रांति की अवस्था में पहुँच गया है. देश की अधिकतर आबादी भूमिहीन किसानों और खेतिहर मजदूरों की हैं. किसानो की दरिद्रता उत्पादन में ह्रास का कारण बन रही है और कांग्रेस और पुलिस से मिली सहायता से सूदखोर किसानो को लूट रहे हैं. यह गहरे कृषि संकट का स्रोत है जिसे सरकार समाधान करने में अक्षम है. कांग्रेस का प्रभाव कम हो रहा है. इन परिस्थितियों में कृषि प्रश्न का एक समुचित समाधान निकालना जरुरी है.

मई १९५० में तैयार किये गए पार्टी दिशा को कई पार्टी संगठन इस आलोक में देखते है: पार्टी के जुझारू सदस्यों के बीच से छोटे- छोटे हथियारबंद समूह बनाया जाये, जमींदारों को मार दिया जाए और तब जंगलो में जा कर छिप जाया जाये. जो जमींदार बच जायेंगे वें भय बस किसानो की मांगे मान लेंगे या

फिर वे पुलिस को बुलायेगें. परिणामस्वरुप किसान राजकीय आतंक का विरोध करना सीखेगे; पुलिस दिन में अपना हुकूमत चलाएगी और हम रात में. और जब सारा देश इस तरह के संघर्ष के प्रभाव में होगा, हम कृषि क्रांति पूरा करें लेंगें, हमारे पास एक मुक्ति सेना होगी और मुक्त क्षेत्र नियंत्रण में होंगे.

मेरा विरोध यह था कि वर्तमान परिस्थिति के अंतर्गत हथियारबंद संघर्ष राजनीतिक दुस्साहस के सिवा कुछ नहीं है और कि हमें लोगो को एकताबद्ध करने के लिए आवश्यक संघर्ष के दूसरे रूपों पर भी ध्यान देना चाहिए और कि यही हथियारबंद संघर्ष का रास्ता प्रसस्त करेगा. हमारी पार्टी के के. स. की दिशा एक नये रूप में चरम-वाम दुस्साहसवाद है. हममे से बहुत इस तरह बातें करते है मानो क्रांति के आरम्भ करने में बस कुछ दिन या माह ही बाकी है. जिस प्रश्न को नजरंदाज कर दिया जाता है वह यह है कि क्या हमारी पार्टी के पास हथियारबंद संघर्ष को मुख्य संघर्ष के रूप में पूर्व निधारित दिशा में पूरा करने के लिए प्रयाप्त ताकत है. और जब मै के. स. के इस दिशा की आलोचना करता हूँ, मुझे अवसरवादी करार दिया जाता है मानो देश में फासीवादी तरीके के आतंक का अस्तित्व हथियारबंद संघर्ष को न्यायोचित ठहराता हो. ऐसा कहना सही नहीं है कि पूरा देश फासीवादी आतंक के चंगुल में है, कि गृह युद्ध की परिस्थितियां भारत में मौजूद है और कि इन परिस्थितियों में चुनाव में भाग लेना हमारे लिए अनावश्यक है और हमे बस अपने आपको हथियारबंद करना चाहिए. मै समझता हूँ यह सही नहीं है.

मैंने हमेशा तेलंगाना में हथियारबंद संघर्ष के पक्ष में बोला है. मुझे लगता है कि देश में आर्थिक संकट से मुस्लिम शासन के अधीन सबसे पिछड़े सामंती रियासत - तेलंगाना में इस तरह के संघर्ष को संगठित करने में मदद मिलेगी. उचित समय पर ही किसी को हथियार उठाना चाहिए और तेलंगाना और आंध्र के

अनुभव का यांत्रिक सामान्यीकरण एक असामयिक विद्रोह की तरफ हमें ले जायेगा. तेलंगाना और आंध्र में जो कुछ भी किया गया है उसके बारे में हमें केवल बहुत सामान्य शब्दों में जानकारी है और कई साथियों द्वारा उन क्षेत्रो को जनवादी गंणतंत्र के रूप में चित्रित किया जाता है. साथ ही, हमे इन क्षेत्रों में हासिल की गयी सफलताओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

मै यह भी कहना चाहता हूँ कि के. स. को अपने सांगठनिक इकाई में नौकरशाही के चलन का खात्मा करना चाहिए और जनवादी रास्ते पर चलना चाहिए. मुझ पर गलत तरीके से आरोप लगाया गया है, मेरे खिलाफ एक गुटीय मुहिम छेड़ दी गयी है जब कि साथ ही साथ वामपंथी राजनीति के समर्थकों को पार्टी में शामिल किया गया है. पार्टी कोष रोकने का, पार्टी की सम्पति सरकार को देने का, आदि आदि हम पर झूठें आरोप लगायें गएँ हैं, कुछ मतभेद जो उभर कर सामने आयें हैं उनका समाधान किया जा सकता है लेकिन बहुत सारे गंभीर मतभेद अभी भी बरक़रार हैं.

मैं निम्न सवालों पर स्पष्टीकरण चाहता हूँ:

औपनिवेशिक और अर्द्ध-औपनिवेशिक देशों में भूमि के राष्ट्रीयकरण के सवाल हमे कैसे खड़े करने चाहिए?

नेहरू की सरकार और उसके विदेश नीति की प्रकृति क्या है? क्या नेहरू सरकार को च्यांग काई शेक और फ्रांसिसी सरकार की तरह ही कठपुतली माना जा सकता है और उन्हें अमेरिकी साम्राज्यवाद की कठपुतली के रूप में देख सकते हैं?;

कैसे, खास तौर से कोरियाई समस्या पर, सरकारी हलकों में मतभेदों और अस्थिरता का फायदा उठाया जाये ?

जैसा की कुछ साथियों ने प्रस्तावित किया है, क्या हमें उन कम्युनिस्टों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान रखना चाहिए यदि पार्टी के प्रति उनकी ईमानदारी और वफादारी पर संदेह हो? हाल ही में ऐसा एक प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन सजा नहीं दी गयी क्योकि बाद में पता चला कि वह कामरेड एक ईमानदार कम्युनिस्ट था. ऐसी आशंका है कि इस तरह की सजा का इस्तेमाल गुटीय उद्देश्य के लिए किया जा सकता है.

क्या हथियारबंद संघर्ष के दौरान भारत में कम्युनिस्टों को भी सत्ता के अपने खुद के अंगों को बनाने से पहले क्रांतिकारी संघर्ष की जरूरतों के लिए जमींदारों और व्यापारियों की संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए?

कामरेड राव: राष्टीय कांग्रेस बिखर रहा है और लोगो पर अपना प्रभाव खो रहा है. मध्यम वर्ग के लोगो में सोवियत और चीन विरोधी भावनाएं भी कम हो रही है. समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से दूर हट रही जनता पर अपना प्रभाव बढाया है और हड़ताल का नेतृत्व करने को मजबूर हुई है, हालाँकि यह सब कुछ गांधीवादी अहिंसा के दायेरे में रह कर किया गया है और मजदूर वर्ग पर इस कार्यनीति को थोपा गया है. शांति के लिए संघर्ष के प्रश्न पर, कोरिया के प्रश्न पर और मजदूर संगठनों की गतिविधियों के तालमेल के प्रश्न पर वाम दल कम्युनिस्टों के साथ एक गठबंधन बनाने को तैयार है. बिना छापामार संघर्ष को संघर्ष का मुख्य रूप बनाये हम आगे नहीं बढ़ सकते. हमारा देश कृषि क्रांति की अवस्था में है. यह सोचना गलत होगा कि हमें पहले एक पार्टी बनाने और एक जनवादी मोर्चा बनाने की जरुरत है और तब हथियारबंद संघर्ष शुरू करना है. हमारे अनुभव इसके उल्टा है. क्रूर दमन को देखते हुए एक जनवादी मोर्चा हथियारबंद संघर्ष के जरिये ही बनाया जा सकता है और इस प्रक्रिया में हमारा पार्टी संगठन स्थापित और मजबूत होगा. जीवन ने हमें दिखाया है कि हमें हथियारबंद संघर्ष

जारी रखना चाहिए जैसाकि कुछ क्षेत्रो में इसका विस्तार भी हुआ है. हमें खुद आश्चर्य हुआ था जब हमें मालूम हुआ कि किसानो ने इस क्षेत्र में हमारे द्वारा भेजे गए इकाइयों को मजबूत समर्थन देने की पेशकश की थी. उन्होंने उन्हें रसदों और सभी अन्य जरुरी मदद प्रदान की जो उनकी गतिविधियाँ चलाने के लिए आवश्यक थी. जनता की सहायता से हमें फासीवादी ताकतों को जरुर कुचलना चाहिए और तभी हम जनता के विश्वास को जीत पायें गे. हथियारबंद संघर्ष से अलग होने पर हम किसी भी दूसरी बड़ी गतिविधियां चलाये बिना केवल प्रचार कार्य करने के लिए मजबूर हो जाएँगे.

मुझे लगता है कि देश में हमारे संघर्ष को तीन चरणों से क्रमवार गुजरना होगा: बड़े पैमाने पर छापामार कार्रवाई, मुक्त क्षेत्र का निर्माण (तेलंगाना और दुसरे क्षेत्रो में), पूरे भारत की मुक्ति.

डांगे और घोष हथियारबंद संघर्ष का विरोध करते है. यह एक सुधारवादी रास्ता है. हम छापामार प्रतिरोध को देश के किसी भी हिस्से में नकारते नहीं है. आम जनता मुख्य कारक हैं, और यदि लोग आगे चलते हैं तो हमे उनका समर्थन करना चाहिए और एक बड़ी पार्टी की स्थापना होने तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए.

चीनी क्रांति के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को नकारना गलत होगा. मुक्देन के पतन का सभी भारतीयों ने स्वागत किया था. डांगे और घोष हथियारबंद संघर्ष के प्रश्न को जनता के बीच चर्चा के लिए नहीं लाना चाहते.

मैं कामरेड डांगे और घोष के लिए निम्न प्रश्न खड़ा करना चाहता हूँ:

क्या आप लोगों के सामने सशस्त्र संघर्ष के प्रश्न प्रस्तुत करने को तैयार हैं?

क्या उन प्रदेशों में जंहा अभी हथियारबंद संघर्ष अस्तित्व में नहीं है, आप हथियारबंद संघर्ष निकट भविष्य में होने से नकारते है.

वहां जहाँ सरकार ने आतंकी राज्य स्थापित किया है और जंहा हम मजबूत है, उदहारणस्वरुप केरल में, आप किस तरह की कार्यनीति का समर्थन करते है?

किन प्रदेशों में एक हथियारबंद संघर्ष की संभावना मौजूद है.

कामरेड डांगे ने बॉम्बे में आम हड़ताल का नेतृत्व प्रदान करने पर ध्यान नहीं दिया. यह गलत था और इसने अन्य दलों को हड़ताली श्रमिकों को अपने तरफ आकर्षित होने दी। मुझे लगता है की वर्तमान में शहरो में सशस्त्र विद्रोह और एक सामान्य राजनीतिक हड़ताल की कार्यनीति संभव नहीं है.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के के. स. के सदस्यों ने चर्चा के दौरान हमारे द्वारा उठाये गए प्रश्नों पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

प्रश्न: हम अपने फ़्रांसिसी और इटालियन साथियों के हवाले से जानते है कि कामरेड डांगे के खिलाफ विशेष मामला बनाया गया था. उनपर आरोप क्या था, मोकदमा ख़त्म कैसे हुआ, क्या कोई समापन दस्तावेज़ है और क्या आप हमें उपलब्ध करा सकते है?

कामरेड राव: डांगे के बारे में प्रश्न पर के. स. की पिछली बैठक में विचार किया गया था. बहुत लोग सोचते थे कि रणदिवे का युगोस्लाव से सम्बन्ध था. आरोप को ख़ारिज करते हुए रणदिवे ने कहा था कि अगर किसी का सम्बन्ध युगोस्लाव से है तो वे डांगे है जिनका सम्बन्ध उस अंग्रेज लड़की से था जिसे डांगे के सिफारिश पर काम करने के लिए भेजा गया था. रणदिवे ने बहुत से दूसरे आरोप भी डांगे के खिलाफ लगायें थें. के. स. का एक जाँच दल नियुक्त किया

गया था जिसने डांगे के खिलाफ आरोपों की जाँच की और उन आरोपों को आधारहीन पाया. लड़की युगोस्लाव में नहीं बल्कि दिल्ली में चेकोस्लोवाकियाई दूतावास में काम कर रही है. रणदिवे द्वारा उल्लेख किये गए पतों के बारे में आरोप भी आधारहीन थे क्योकि कोई भी पता रणदिवे द्वारा निर्दिष्ट डायरी में नहीं पाया गया था.

कामरेड पुन्नैया: मैं कुछ जोड़ना चाहूगा क्योकि मैं इस समिति का एक सदस्य था. भाकपा में टिटोवादियों की घुसपैठ के बारे में प्रश्न के साथ-साथ पार्टी के बॉम्बे समिति के टिटो से कड़ियों के उजागर के बाद भी कायम सम्बन्ध के प्रश्न पर विचार किया जाना था. रणदिवे ने दलील दी कि कामरेड डांगे द्वारा इन संबंधो को प्रोत्साहित किया गया था. समिति ने इन आरोपों की जांच की और इन आरोपों को निराधार पाया.

प्रश्न : हम जानते है कि सरकार के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष पर विचार करते समय के. स. भाकपा ने चीन के सम्बन्ध में सरकार की विदेश नीति का समर्थन किया था. शायद आप सही कह रहे हो पर हम आपसे स्पष्टीकरण चाहते है कि कैसे उस तरह के आह्वान को आप अपनी आम दिशा से सामंजस्य करते है?

प्रश्न के उत्तर में कामरेड डांगे ने कहा: हमारे रवाना होने से पहले परमाणु बम के उपयोग के बारे में ट्रूमैन के बयान के संबंध में प्रश्न पर बम्बई में हमलावर के रूप में चीन की निंदा करने के नेहरू की नीति की पुष्टि करते हुए हमारे द्वारा एक मसौदा बयान तैयार किया गया था। लेकिन हमने इस बयान पर चर्चा या इसके प्रकाशन के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया. संभवत: मुंबई में साथियों ने स्वतंत्र रूप से इसे प्रकाशित करने का निर्णय लिया। हम पहले से ही

भारत में नहीं थे। हमें आगे इस बयान की सामग्री के बारे में सोचने की जरूरत है।

कामरेड राव, घोष और पुन्नैया: ने कॉम डांगे द्वारा दिए गए उत्तर के साथ सहमति व्यक्त की.

प्रश्न : आपने हमें अपने बीच गंभीर मतभेद के बारे में बताया और साथ ही के. स. के दिसम्बर सभा में, जंहा ये मतभेद प्रबल हुए, कामरेड घोष और डांगे को पोलित ब्यूरो में लाया गया. हम जानना चाहते है कि किस सिद्धांत के आधार पर पोलित ब्यूरो के गठन में ये बदलाव लाया गया.

उत्तर: पोलित ब्यूरो में परिवर्तन के बारे में टिप्पणियों का जवाब देते हुए कामरेड घोष ने कहा: पोलित ब्यूरो के गठन में बदलाव के लिए ९ व्यक्तियों का के. स. एकमत था. जब हम जेल से बाहर आये, हमने के.स. के राजनितिक दिशा की आलोचना करते हुए एक दस्तावेज़ तैयार किया. तब पार्टी को टूट से बचाने के लिए यह तय हुआ कि दोनों प्रवृतियों के प्रतिनिधियों को ले कर के. स. और पोलित ब्यूरो बनाया जाये.

कामरेड राव, डांगे और पुन्नैया ने उत्तर के साथ सहमति व्यक्त की।

प्रश्न: क्या भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के पास अपने स्वयं के कार्यक्रम और संविधान है?

उत्तर:

कामरेड डांगे : हमारी पार्टी का अपना कार्यक्रम नहीं है।

कोमिन्टर्न में हिस्सा लेने के समय १९२९ में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक "भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यों का मसौदा मंच" प्रस्तुत किया था

जिसके आधार पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को कोमिन्टर्न का हिस्सा बनने की अनुमति मिली थी. हालांकि, वर्तमान में हम उस मंच को अपना कार्यक्रम नहीं मानते.

जंहा तक संविधान की बात है, १९४३ में पार्टी के प्रथम कांग्रेस में पार्टी का संविधान अपनाया गया था. १९४८ में पार्टी की द्‌वितीय कांग्रेस में संविधान की समीक्षा की गई और कुछ बदलाव के साथ मंजूरी दे दी गयी थी.

कामरेड राव, घोष और पुन्नैया: ने इस बात की पुष्टि की.

प्रश्न: क्या आप अधिक से अधिक विस्तार से भारत में चल रहे छापामार आंदोलन के बारे में हमें बता सकते हैं. छापामार युद्ध किन क्षेत्रों में और किसके विरुद्ध चलाया जा रहा है? उसका पैमाना क्या है, क्या कोई बड़े पैमाने का क्षेत्र है जिसे छापामारों द्‌वारा मुक्त कराया गया हो, छापामारों ने कहाँ अपनी स्थिति मजबूत की है और क्या जनता की जनवादी सत्ता के अंगो का निर्माण किया है? तेलंगाना और आंध्र में वास्तविक स्थिति क्या है, जहाँ, जैसा कि आपने कहा है, छापामार आन्दोलन सबसे विकसित है और किस तरह के हथियारों से ये छापामार लैश है?

उत्तर:

कामरेड राव: छापामार आंदोलन मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र के प्रदेशों में हो रहा है।

तेलंगाना में १९४८ तक हैदराबाद में भारतीय सेना के आने से पहले नियमित रूप से छापामार इकाइयाँ सक्रीय थी जिनकी कुल संख्या २ हजार हथियारबंद व्यक्तियों की थी. बहुत ही कम हथियारों से वे लैश थे और उनके पास ३० स्वचालित हथियार, २०० राइफलें और बाकी भाले, तलवारें और शिकार करने वाले

हथियार थे. छापामार इकाइयों के खिलाफ सशस्त्र बलों द्वारा उठाए गए मजबूत उपायों के बाद छापामारों की संख्या कम हो गयी. वर्तमान में इन इकाइयों के पास करीब ५०० आदमी है. इकाइयां रात में छोटे समूहों में कार्य करते हैं. वे ५ पुरुषों के समूहों में विभाजित हैं. पार्टी ने उनका समर्थन करने के लिए ४०० राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भेजा है जो सशस्त्र छापे में भाग नहीं लेते लेकिन लोगों के बीच राजनीतिक कार्य का संचालन करते हैं.

अतीत में कभी भी अपनी सत्ता के अंगों के साथ कोई भी मुक्त क्षेत्र नहीं था और कोई अब भी नहीं है.

आंध्र में १९४९ में छापामार इकाइयों में लगभग १००० लोग थे. सरकारी दमन के चलते एक हिस्सा तेलंगाना में चला गया और वर्तमान में कोई भी नियमित छापामार इकाई आंध्र में नहीं है.

कामरेड राव द्वार दिए गए जबाव पर कामरेड घोष ने अपनी टिपण्णी देते हुए कहा कि छापामार आन्दोलन के पैमाने का आकलन करते समय उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की प्रवृति मौजूद रहती है और ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी घटना को विद्रोह के रूप में देखा जाता है.

इस टिपण्णी पर प्रतिक्रिया देते हुए कामरेड पुन्नैया ने कहा कि उन्होंने विदेशी मीडिया से आंकड़ों का इस्तेमाल किया है क्योकि भाकपा के. स. के पास प्रादेशिक पार्टी समितियों से कोई जानकारी नहीं है.

प्रश्न: भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा सेना में क्या काम किया जा रहा है और सेना में इसका क्या प्रभाव है?

उत्तर:

कामरेड राव : पार्टी ने सेना में कोई काम नहीं किया है और वहां इसका प्रभाव नहीं है. पार्टी का कुछ हद तक वायु सेना और जल सेना में प्रभाव है.

किसानो की सक्रियता को दबाने के लिए सरकार एक नियम के तहत दूसरे प्रदेशों से सेना भेजती है जो वहां की भाषा नहीं जानते जहाँ घटना होती है. सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नेहरू सरकार और नेपाल की सरकार के बीच एक विशेष समझौते के तहत नेपाल में भर्ती किया जाता है.

टाइपप्रति

RGASPI F.558 Op. 11 D.310 LL. 12-32.

सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के रूसी राज्य अभिलेखागार के अधिकारियों की रज़ामंदी से प्रकाशित.

ताहिर असगर द्वारा मूल रूसी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद

रिवोल्युशनरी डेमोक्रेसी, वॉल्यूम बारहवीं, नंबर 2, सितम्बर 2006 में प्रकाशित

अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद- प्रोलेतेरियन क्रिटिक

वेब संस्करण http://www.proletariancritique.blogspot.in